श्री नन्द किशोर यादव : सर, बैकबेंचर्स को आपका संरक्षण चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : संरक्षण हमेशा है, लेकिन एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री नन्द किशोर यादव : सर, इस देश में जो तमाम तरह की निधियां हैं, करीब 110 लाख करोड़ के आसपास हैं, ये निधियां हैं, इनमें सड़क विकास निधि, रेलवे सुरक्षा निधि, रक्षा निधि, पेंशन निधि, कर्मचारी कल्याण निधि इत्यादि है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन निधियों को देश की मुख्यधारा में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे में सुधार होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बता देना चाहूंगा कि मुझे अर्थशास्त्र और फाइनेंशियल सिस्टम की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लंबे अरसे से एक पोलिटिकल वर्कर और सोशल वर्कर के रूप में समाज के बीच में काम करने का जो मौका मिला है, उसके आधार पर ही देश की जो आर्थिक नीति है, जिसकी झलक इस बजट में मिलती है, उसको देखता हूं। अभी हमारे मित्र रवि शंकर प्रसाद जीने कहा कि प्रणब बाबू जो बजट पेश कर रहे हैं देश बहुत उत्सुकता के साथ उसको देख रहा है। मैं इस मामले में उनके साथ सहमत नहीं हूं। इस देश के आम आदमी को बजट से क्या मतलब है? देश की आर्थिक स्थिति, देश की आजादी के बाद लगातार जो बजट पेश किए जाते रहे हैं, उनसे इस देश के आम आदमी की हालत सुधरी नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं कि उसकी हालत बिगड़ी है। उसे लगता है कि आजादी के इतने बरस बाद हमें अब ठहरकर देखना चाहिए कि आजादी के बाद जिन आर्थिक नीतियों को हम चलाते रहे, उन नीतियों की वजह से देश में गरीबी घटी है, देश में बेरोजगारी घटी है, देश में भ्रष्टाचार घटा है, यह जांचने, परखने का समय आ गया है। मैं यह मानता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ इस देश में जो जंग हुई थी और हमारी आजादी के नायकों ने देश के लोगों के साथ जो वायदा किया था, उसकी वायदाखिलाफी हुई है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मानिएगा कि हमारी आजादी के संघर्ष के मुख्य नायक महात्मा गांधी थे। उन्होंने ही आजादी के बाद देश की तस्वीर क्या होगी, आजादी के बाद देश की आर्थिक नीति क्या होगी, इसके बारे में जनता को शिक्षित करने और बताने का काम किया था। आजादी के बाद देश की आर्थिक नीति क्या होगी, इस संबंध में मैं गांधी जी के शब्दों को कोट करके आपके सामने रखना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जिस तरह सच्चे नीति धर्म में और अच्छे अर्थ शास्त्र में कोई विरोध नहीं होता...। "...जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाता है और बलवानों को निर्बलों का शोषण करके धन का संग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता है।" यह महात्मा गांधी ने कहा है। आगे उनका कहना है, "आर्थिक समानता के लिए वह तो एक झूठी चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे अपना कर हम मृत्यु को न्यौता देंगे। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय की हिमायत करता है, वह समान भाव से सबकी भलाई का, जिनमें कमजोर भी शामिल हैं, प्रयत्न करता है।" यह गांधी जी का कहना है। आज तक हमारे देश में जो आर्थिक नीति चली है, अगर इस कसौटी पर हम उसे जांचने और परखने का काम करेंगे, तो पता चलेगा कि हम देश में जो आर्थिक नीति चला रहे हैं, वह नैतिक नहीं, अनैतिक है। इसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इस देश में एक से बढ़ कर एक स्कैंडल्स हो रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी परसों-नरसों यहां Information and Technology Ministry के बारे में चर्चा हो रही थी और लीडर ऑफ ऑपोजीशन सहित कई लोगों ने संदेह जताया, मंत्री से pointed सवाल किया कि इसमें 60-70 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। मैं भी यहां बैठा सुन रहा था और मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था। आज के अखबारों में भी खबर छपी है, जिसमें बताया गया है कि कारपोरेट सेक्टर में लड़ाई हो रही है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सरकार 50 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा देने जा रही है। यही आर्थिक नीति इस देश में चल रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई मुंह से अंदाज पर नहीं बोल रहा हूं, आप आंकड़ों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो इस देश में गरीबी बढ़ रही है। अभी इसी 24 जुलाई को ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी के सवाल के जवाब में खुद सरकार ने माना है और बताया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 2007-08 के अनुसार इस देश में 69.5 प्रतिशत बच्चे, जिनमें 71.5 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे और 73 प्रतिशत शहरी बच्चे और 15-49 वर्ष की आयु की 55.3 प्रतिशत महिलाएं रक्त-अल्पता की शिकार हैं, anemic हैं। यह अभी 24 जुलाई को बताया गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश की हालत है। हमारे देश की अधिकांश महिलाएं, अधिकांश बच्चे anemic हैं, उनमें खून की कमी है, उनका वजन घट रहा है। हम गर्भवती महिलाओं को अच्छी खुराक नहीं दे पाते हैं। यह मेडिकल साइंस के जरिए साबित है कि जब गर्भ में बच्चे का formation होता है, आगे चल कर वह किस तरह का आदमी बनेगा, किस तरह का बच्चा बनेगा, यह उसी समय decide हो जाता है। हमारे देश के अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनकी height नहीं बढ़ रही है, उनका mental development नहीं हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हम दुनिया में एक आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में हालत क्या है? 1956-57 में प्रति व्यक्ति दाल की खपत 72 ग्राम थी। आप जानते हैं कि दाल ही गरीब आदमी के प्रोटीन हासिल करने का जरिया होता है। गरीबों के बीच यह कहावत थी कि हम दाल-रोटी खाने वाले जीव हैं। उस दाल की आज क्या हालत है! 1956-57 में देश के आजाद होने के बाद नई-नई बात थी, उस समय हम 72 ग्राम दाल खाते थे, 1990-91 में दाल की खपत प्रति व्यक्ति 42 ग्राम हो गई और 2005-06 में 33 ग्राम। आज हमें नहीं मालूम है कि यह 33 ग्राम दाल भी कई थालियों से, जिस ढंग से दाल का हम अखबारों में पढ़ते हैं, अधिकांश थालियों से दाल गायब हो चुकी है। आजादी के इतने वर्षों के बाद हम जो आर्थिक नीति चला रहे हैं, यह उसकी उपलब्धि है! यही नहीं, जो अनाज है, गेहूं है, चावल है, उनकी भी प्रति व्यक्ति खपत इस देश में घटी है।

महोदय, हमारे देश के किसानों की क्या हालत है? स्वामीनाथन जी कहते हैं कि जब हम खेती की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 70 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उन 70 करोड़ लोगों की क्या हालत है? नमो नारायण मीणा जी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि उनके अनुसार पिछले 30 वर्षों में ग्रामीण परिवार पर कर्ज का बोझ 25 गुना बढ़ गया है। 1971 में प्रति ग्रामीण परिवार औसत कर्ज 487 रुपए था, जो 2003 में 12,585 करोड़ रुपए हो गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, यही हमारे देश की आर्थिक नीति की उपलब्धि है। मैं यह कह रहा था कि जिन आर्थिक नीतियों को हम चला रहे हैं, उनसे हम क्या हासिल कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इस सरकार को बहुमत मिला है, हमको इसमें एक बात अच्छी लगी। जब सरकार ने शपथ ग्रहण की थी, उससे पहले अखबारों में खबर छपती थी कि फाइनांस मिनिस्टर कोई टेक्नोक्रैट होगा। हमें इस बात की खुशी है कि प्रणब दा फाइनांस मिनिस्टर बने हैं, कोई टेक्नोक्रेट नहीं बना है। क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया गया था, उस आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने के बाद यह डर लग रहा है कि हमारी जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनका भी विनिवेश हो जाएगा, और तो और बैंक भी प्राइवेट सैक्टर में चले जाएंगे। हमें इस बात का डर लग रहा था, लेकिन मैं हमेशा यह पसंद करता हूं कि कोई टैक्नोक्रेट आदमी फाइनांस मिनिस्टर बने, उससे बेहतर है कि पब्लिक लाइफ का कोई आदमी इस मंत्रालय का काम संभाले।

एक माननीय सदस्य : आपकी बात एन.के. सिंह जी को अच्छी नहीं लग रही होगी।

श्री शिवानन्द तिवारी : प्रणब मुखर्जी जी ने ...(**समय की घंटी**)...